



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 6-2022] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2022 (MAGHA 19, 1943 SAKA)

PART - I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सचिवालय स्थापना

अधिसूचना

दिनांक 10 जनवरी, 2022

संख्या 22/15/2021-6स्था-1.— राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, अनुसूचित जाति समुदाय के कर्मचारियों के लिए एतद्वारा एक आन्तरिक शिकायत निवारण समिति हरियाणा सचिवालय के लिए निम्न रूप से गठित की जाती है, जिस द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने और रोजगार/सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण की सुनवाई की जाएगी :-

1. श्री अनुराग अग्रवाल, भा० प्र० से० : अध्यक्ष
 2. श्री डी. सुरेश, भा० प्र० से० : सदस्य
 3. श्री ए. श्रीनिवास, भा० प्र० से० : सदस्य
 4. श्री आर.सी. बिधान, भा० प्र० से० : सदस्य
 5. श्रीमती वर्षा खंगवाल, ह० सि० से० : सदस्य
2. आंतरिक शिकायत निवारण समिति सेवा मामले में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की शिकायतों की जाँच करेगी जिनमें निम्न शामिल है :-
1. आरक्षण रॉस्टर का रखरखाव न करना और आरक्षित रिक्तियों को न भरना
 2. पदोन्नति/वरिष्ठता/एम०ए०सी०पी० में भेदभाव
 3. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति न करना
 4. ए०पी०ए०आर०/ए०सी०आर०/डाउनग्रेडिंग
 5. सेवा से बर्खास्तगी/निष्कासन
 6. स्थानान्तरण/नियुक्ति में भेदभाव
 7. पेंशन संबंधी लाभों से इन्कार और बकाया वेतन का भुगतान आदि।
3. समिति शिकायत की सत्यता का पता लगाने के लिए शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तरदायी होगी और साथ ही समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट संगठन प्रमुख को सौंपेगी और शिकायत का समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करेगी।

4. आंतरिक शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।
5. आंतरिक शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को आंतरिक शिकायत निवारण समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए ऐसी फीस या भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
SECRETARIAT ESTABLISHMENT

Notification

The 10th January, 2022

No. 22/15/2021-6Estt.-I— In pursuance of recommendation of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), an Internal Grievance Redressal Committee for employees belonging to Scheduled Castes community is hereby constituted for the Haryana Civil Secretariat comprising of following members with a view to provide safeguards to the Scheduled Caste persons and for hearing the grievances relating to employment/services of Scheduled Caste employees of Haryana Civil Secretariat and redressal thereof:—

- | | | | |
|----|---------------------------|---|----------|
| 1. | Sh. Anurag Agarwal, IAS | : | Chairman |
| 2. | Sh. D. Suresh, IAS | : | Member |
| 3. | Sh. A. Sreenivas, IAS | : | Member |
| 4. | Sh. R.C. Bidhan, IAS | : | Member |
| 5. | Smt. Varsha Khangwal, HCS | : | Member |

2. The Internal Grievance Redressal Committee shall examine the complaints received from SC employees in service matters including:—

- Non-maintenance of reservation roster and not filling up of reserved vacancies.
- Discrimination in promotion/seniority/MACP/ACP.
- Non-appointment on compassionate grounds.
- Downgrading of APARs/ACRs.
- Termination/ dismissal from services.
- Discrimination in transfer/posting.
- Denial of pensionary benefits and disbursement of pay arrears etc.

3. The Committee will examine the complaints to find out the genuineness of the complaint and will submit its report within one month to the Head of Organization and ensure time bound redressal of the complaint.

4. The Chairman and every Member of the “Internal Grievance Redressal Committee” shall hold office for period not exceeding three years, from the date of his/her nomination.

5. The Chairman and every Member of the “Internal Redressal Complaint Committee” shall not be paid any fees of allowances for holding the proceedings of the “Internal Redressal Complaint Committee”.

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government Haryana.